

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

प्रश्न 1. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को कैसे परिभाषित किया गया है?

उत्तर. सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत दिए गए अधिकारों और संहिता के तहत बनाई गई योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों, जिनमें असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक शामिल हैं, को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने और विशेष रूप से बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, काम की चोट, मातृत्व या कमाने वाले की मृत्यु के मामलों में आय सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिए जाने वाले सुरक्षा के उपाय।

प्रश्न 2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में कितने विधान समिक्षित/समामेलित हैं और वे कौन से हैं?

उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में नौ केंद्रीय श्रम विधान समामेलित हैं, यानी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952; रोजगार कार्यालय (रिकियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; सिनेमा कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981; भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।

प्रश्न 3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य क्या है?

उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य संगठित या असंगठित क्षेत्र से संबंधित सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के व्यापक लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा श्रम कानूनों को संशोधित और समेकित करना है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, जीवन बीमा और विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, भविष्य निधि सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के उद्देश्य से स्व-रोजगार श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों, मजदूरी श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कवर करती है।

प्रश्न 4. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत किन सामाजिक सुरक्षा संस्थानों की परिकल्पना की गई हैं?

उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2(79) सामाजिक सुरक्षा संगठनों का उल्लेख करती है। इसमें क) धारा 4 के तहत गठित कर्मचारी भविष्य निधि का केंद्रीय न्यासी बोर्ड; (ख) धारा 5 के तहत गठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम; (ग) धारा 6 के तहत गठित असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड; (घ) धारा 6 के अंतर्गत गठित राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड; (ङ) धारा 7 के तहत गठित राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड; और (च) केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संगठन के तौर पर घोषित कोई अन्य संगठन या विशेष प्रयोजन साधन शामिल हैं।

5. क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत ईपीएफ और ईएसआई अध्यायों के संबंध में प्रतिष्ठानों के कवरेज के संबंध में बाहर निकलने या चुनने का कोई विकल्प है?

उत्तर. हाँ, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 1(5) के तहत स्वैच्छिक कवरेज की अनुमति दे सकता है। बाहर जाने का विकल्प उपलब्ध है और नियम 3 प्रक्रिया का पालन किया जाना है। दोनों स्थितियाँ नियोक्ता और अधिकांश कर्मचारियों के बीच समझौते पर आधारित हैं। इस पर निर्णय लेने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत 60 दिनों की समय सीमा प्रदान की गई है। या फिर एक मान्य प्रावधान (आवेदन को अनुमति के रूप में माना जाता है) लागू होता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय III के प्रावधानों के तहत इस तरह के कवरेज के पांच साल से पहले प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा ऐसा कोई आवेदन (ऑप्ट इन/ऑप्ट आउट) नहीं किया जाएगा। ऐसे किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी वैधानिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए हैं, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत सभी वैधानिक बकाया का भुगतान नहीं किया है और आवेदन के साथ इस आशय का स्व-प्रमाणन जमा नहीं किया है। जहां तक ईएसआई पर अध्याय (अध्याय IV) का सवाल है, इस प्रकार के आवेदन पर निगम के महानिदेशक द्वारा निर्णय लिया जाना होता है (नियम 3 लागू होता है)। यहां भी, निर्णय के लिए 60 दिनों की समय सीमा प्रदान की जाती है (इस संदर्भ में धारा 1(7)एवं परंतुक लागू है)।

6. क्या ऐसा कोई आधार हो सकता है जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत प्रतिष्ठानों को अध्याय III (ईपीएफ) और अध्याय-IV (ईएसआईसी) की प्रयोज्यता से छूट दी जाए?

उत्तर. हाँ, छूट का आधार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के नियम 60 के साथ पठित धारा 143 के तहत है। ये आधार निम्नवत हैं:

- (क) प्रतिष्ठान ईएसआई और ईपीएफ अध्यायों के तहत दिए गए लाभों के समान या बेहतर लाभ प्रदान कर रहे हैं;
- (ख) छूट चाहने वाला प्रतिष्ठान इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा आवेदन करेगा;
- (ग) प्रतिष्ठान आवेदन करने से ठीक पहले लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए अध्याय III और IV के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है और ऐसी अवधि के दौरान संबंधित अध्यायों के तहत देय योगदान के भुगतान में चूक नहीं की है;
- (घ) ऐसे आवेदन की तिथि पर, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय III और IV, जैसा भी मामला हो, के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम पांच सौ अंशदायी सदस्य हों;
- (ङ) भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना के प्रावधानों से छूट चाहने वाले प्रतिष्ठान के पास उस योजना के संबंध में सदस्यों के खाते में पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का संचयी शेष होना चाहिए, जिससे छूट मांगी गई है;
- (च) ईपीएफ उद्देश्यों के लिए प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए अधिकांश कर्मचारियों की सहमति प्रस्तुत करेगा;

- (छ) छूट चाहने वाले प्रतिष्ठान के पास आवेदन की तारीख से पहले पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान धनात्मक निवल मूल्य होना चाहिए;
- (ज) प्रतिष्ठान को संबंधित डेटा-बेस में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय III और अध्याय IV, जैसा भी मामला हो, के प्रयोजनों के लिए संबंधित सदस्यों के खाते में प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या दर्ज करनी होगी;
- (झ) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय III के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठान ऑनलाइन दावा निपटान के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और छूट मिलने के नब्बे दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ जुड़ाव प्रदान करने के लिए शिकायत समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा।

7. क्या अध्याय IV (ईएसआई लाभ) के प्रावधानों और लाभों को एकल कर्मचारी को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ। इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित खतरनाक या जीवन को खतरे में डालने वाले व्यवसायों पर लागू किया जा सकता है, जिसमें एक भी कर्मचारी कार्यरत है।

8. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में उल्लिखित कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी क्या है?

उत्तर. राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 40 की उप-धारा (5) के संदर्भ में कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के रूप में ऐसा संगठन स्थापित कर सकती है, जो एक प्रबंधकीय और स्वास्थ्य देखभाल निकाय के रूप में काम करेगी। सोसायटी में शासी निकाय (त्रिपक्षीय), कार्यकारी समिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सचिवालय शामिल होंगे। सोसायटी को राज्य विशिष्ट सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और राज्य विशिष्ट सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

9. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत 'ग्रेच्युटी' अध्याय के अंतर्गत कौन से प्रतिष्ठान शामिल हैं?

उत्तर. 'ग्रेच्युटी' पर अध्याय निम्नांकित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है:

- क) प्रत्येक कारखाना, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और रेलवे कंपनी; और
- ख) प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, या कार्यरत थे; और
- ग) ऐसी दुकानें या प्रतिष्ठान जिन्हें उचित सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

10. वे कौन सी स्थितियाँ हैं जिनके तहत सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत पांच साल की बेदाग सेवा पूरी करने की ग्रेच्युटी पात्रता में छूट दी जा सकती है?

उत्तर. आम तौर पर तीन स्थितियाँ हैं जिनमें पांच साल की अवधि में छूट दी गई है। वे हैं:

- क) दूर्घटना या बीमारी के कारण कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता पर;

ख) निश्चित अवधि के रोजगार के तहत उसके अनुबंध अवधि की समाप्ति पर (आनुपातिक आधार पर); या

ग) किसी भी ऐसी घटना के घटित होने पर जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

इसके अलावा, वर्किंग जर्नलिस्ट के मामले में विशेष छूट है, जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (एफ) में परिभाषित है, पांच साल के बजाय तीन साल पूरे करने होंगे।

11. ऐसे कौन से प्रकार के भवन/अन्य निर्माण कार्य हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय IX के तहत सामाजिक सुरक्षा पहलुओं पर अध्याय से बाहर रखा गया है?

उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2(6) के अनुसार बाहर रखे गए कार्य हैं: कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य जो किसी कारखाने या खदान या किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित है जिसमें पिछले बारह महीनों में दस से कम श्रमिक कार्यरत हैं या जहां ऐसा कार्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अपने निवास के लिए आवासीय उद्देश्यों से संबंधित है और ऐसे कार्य की कुल लागत पचास लाख रुपये या इतनी अधिक राशि से अधिक नहीं है और ऐसी संख्या से अधिक श्रमिकों को नियोजित करना है जो उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं।

12. लाभार्थियों के रूप में पंजीकरण और लाभार्थी के रूप में समापन की घटनाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत भवन निर्माण श्रमिकों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 106 श्रमिकों के पंजीकरण के बारे में चर्चा करती है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। पंजीकृत श्रमिकों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, जिससे वे अधिसूचित निर्धारित योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। श्रमिकों का पंजीकरण कराना राज्य सरकार और राज्य भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी है।

संहिता की धारा 106 के अनुसार, प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और जो पिछले बारह महीनों के दौरान कम से कम नब्बे दिनों से कम समय के लिए किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगा हुआ है, उसे भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 107 के तहत लाभार्थी के रूप में समापन पर चर्चा की गई है। एक भवन निर्माण श्रमिक जिसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह लाभार्थी नहीं रहेगा जब वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा या जब वह एक वर्ष में कम से कम नब्बे दिनों के लिए भवन या अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत नहीं होगा।

13. क्या एक भवन निर्माण श्रमिक जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करता है, उसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत लाभ मिल सकता है। यदि हाँ, तो कहाँ से?
- उत्तर. हाँ। जहाँ एक भवन निर्माण श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करता है, वह उस बोर्ड से लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह वर्तमान में काम कर रहा है और यह बोर्ड ऐसे श्रमिकों को ऐसे लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
14. एग्रीगेटर कौन है? सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 से जुड़ी सातवीं अनुसूची के तहत किन सभी प्रकार के एग्रीगेटर्स को संदर्भित किया गया है?
- उत्तर. संहिता की धारा 2(2) एग्रीगेटर को किसी सेवा के खरीदार या उपयोगकर्ता के लिए विक्रेता या सेवा प्रदाता से जुड़ने के लिए डिजिटल मैदान स्थान के रूप में परिभाषित करती है। अनुसूची VI I के अंतर्गत सूचीबद्ध एग्रीगेटर हैं: 1. राइड शेयरिंग सेवाएं 2. खाद्य और किराना वितरण सेवाएं 3. लॉजिस्टिक सेवाएं 4. माल और/या सेवाओं (बी2बी/बी2सी) की थोक/खुदरा बिक्री के लिए ई-मार्केट प्लेस (मार्केट प्लेस और इन्वैट्री मॉडल दोनों) 5. पेशेवर सेवा प्रदाता 6. हेल्थकेयर 7. यात्रा और आतिथ्य 8. सामग्री और मीडिया सेवाएं और 9. कोई अन्य सामान और सेवा प्रदाता मंच।
15. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 से जुड़ी अनुसूचियों में कौन और कैसे संशोधन कर सकता है?
- उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 152 (1) इसके संबंध में प्रक्रिया का वर्णन करती है।
केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची में कुछ जोड़ने या हटाने के माध्यम से संशोधन कर सकती है और इस तरह के जोड़ या हटाए जाने पर, अनुसूचियां तदनुसार संशोधित मानी जाएंगी।
उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में कुछ जोड़कर संशोधन कर सकती है, अन्यथा नहीं, और इस तरह के जोड़ पर, अनुसूचियां तदनुसार संशोधित मानी जाएंगी।
16. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत निश्चित अवधि का रोजगार क्या है?
- उत्तर. इसका मतलब एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार के लिखित अनुबंध के आधार पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति है। एक निश्चित अवधि के कर्मचारी के काम के घंटे, वेतन, भत्ते और अन्य लाभ समान काम या समान प्रकृति का काम करने वाले स्थायी कर्मचारी से कम नहीं होंगे; और ऐसा कर्मचारी किसी स्थायी कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से उपलब्ध किसी भी कानून के तहत सभी लाभों के लिए पात्र होगा, भले ही रोजगार की अवधि रोजगार की आवश्यक अर्हता अवधि तक विस्तारित न हो (अर्थात् 5 साल की सेवा की ग्रेच्युटी पात्रता)।
17. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत किसे अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक माना जाएगा?

- उत्तर. धारा 2(41) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत एक "अंतर- राज्यीय प्रवासी श्रमिक" को परिभाषित करती है और इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो एक प्रतिष्ठान में कार्यरत है और जिसे (i) दूसरे राज्य में स्थित ऐसे प्रतिष्ठान में रोजगार के लिए नियोक्ता द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से एक राज्य में ठेकेदार के माध्यम से भर्ती किया गया है; या (ii) एक राज्य से स्वयं आया है और दूसरे राज्य/गंतव्य राज्य के प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त किया है या बाद में ऐसे रोजगार के लिए एक समझौते या अन्य व्यवस्था के तहत गंतव्य राज्य के भीतर प्रतिष्ठान को बदल दिया है और प्रति माह अठारह हजार रुपये से अधिक या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई ऐसी उच्च राशि का वेतन नहीं ले रहा है।
18. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिक कौन है?
- उत्तर. धारा 2 (86) एक "असंगठित श्रमिक" को परिभाषित करती है जिसमें गृह-आधारित श्रमिक, स्व-रोजगार श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाला श्रमिक शामिल है और इसमें संगठित क्षेत्र का वह श्रमिक शामिल है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय III (ईपीएफ पर अध्याय) से VII (कर्मचारी मुआवजे पर अध्याय) के अंतर्गत नहीं आता है।
19. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत 'गिग वर्कर' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर' कौन है?
- उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2(35) "गिग श्रमिक" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है - वह व्यक्ति जो काम करता है या किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर कमाता है।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 (61) 'प्लेटफॉर्म श्रमिक' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है - प्लेटफॉर्म कार्य में संलग्न या उपक्रम करने वाला व्यक्ति और धारा 2 (60) 'प्लेटफॉर्म कार्य' को पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर एक ऐसी कार्य व्यवस्था के रूप में परिभाषित करती है जिसमें संगठन या व्यक्ति भुगतान के बदले में विशिष्ट समस्याओं को हल करने या विशिष्ट सेवाएं या ऐसी अन्य गतिविधियों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, को प्रदान करने के लिए अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
20. असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण कराने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत क्या प्रक्रिया परिकल्पित की गई है?
- उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 113 असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया पर चर्चा करती है। नियम 50 (1) और (2) इसमें शामिल प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं।
- इन प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक या प्लेटफॉर्म श्रमिक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अध्याय-I X (असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा) के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत होना आवश्यक होगा:

(क) उसने सोलह वर्ष की आयु या ऐसी आयु पूरी कर ली है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए;

(ख) उसने इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा स्व-घोषणा ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से प्रस्तुत की है जिसमें ऐसी जानकारी शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

प्रत्येक पात्र असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक या प्लेटफॉर्म श्रमिक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधार संख्या सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और उस श्रमिक को उसके आवेदन के लिए एक विशिष्ट नंबर सौंपा जाएगा। उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण की प्रणाली ऐसे किसी भी श्रमिक द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से स्वयं पंजीकरण के लिए भी प्रावधान करेगी। केवल पंजीकृत असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक या प्लेटफॉर्म श्रमिक सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत बनाई गई संबंधित योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी योजना में ऐसा योगदान करेगी जो उस प्रभाव के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

21. क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत एग्रीगेटर्स से कोई योगदान अनिवार्य रूप से निर्धारित है?

उत्तर. हाँ। धारा 114(4) एग्रीगेटर्स से योगदान एकत्र करने का प्रावधान करती है। संहिता के अनुसार उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने वार्षिक कारोबार का 1 से 2 प्रतिशत योगदान देना होगा, जो कि एग्रीगेटर द्वारा गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भुगतान की गई या देय राशि के 5% से अधिक नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का नियम 51(3) उसी के बारे में बारीकियों पर चर्चा करता है।

22. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत राष्ट्रीय और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के क्या कार्य हैं?

उत्तर. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्य हैं:

(क) असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना;

(ख) इस संहिता के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा जो उसे संदर्भित किए जाएं;

(ग) असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए ऐसी सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करना जो केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित हैं;

(घ) राज्य स्तर पर किए गए रिकॉर्ड रखने के कार्यों की समीक्षा करना;

(ङ) निधि और खाते से व्यय की समीक्षा करना; और

(च) ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के राज्य स्तर पर समान कार्य हैं।

23. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत राज्य भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के क्या कार्य हैं?

उत्तर. राज्य भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्य हैं:

- (क) किसी लाभार्थी या उसके आश्रितों को मृत्यु और विकलांगता लाभ प्रदान करना;
- (ख) साठ वर्ष की आयु पूरी कर चुके लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करना;
- (ग) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करना जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित की जाए;
- (घ) लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक योजनाएं तैयार करना;
- (ङ) किसी लाभार्थी या आश्रित की प्रमुख बीमारियों के इलाज के लिए ऐसे चिकित्सा खर्चों को पूरा करना, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए;
- (च) लाभार्थियों को मातृत्व लाभ का भुगतान करना;
- (छ) लाभार्थियों के लिए कौशल विकास और जागरूकता योजनाएं तैयार करना;
- (ज) लाभार्थियों को पारगमन आवास या छात्रावास सुविधा प्रदान करना;
- (झ) केंद्र सरकार की सहमति से राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के लिए कोई अन्य कल्याणकारी योजना तैयार करना; और
- (ञ) ऐसे अन्य कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, का प्रावधान करना और उनमें सुधार करना।

24. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय III के तहत केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार की योजनाओं को अधिसूचित किया जाना है?

उत्तर. केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

- (क) एक योजना तैयार करना जिसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना कहा जाएगा, जिसके लिए भविष्य निधि कर्मचारियों के लिए या कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के लिए अध्याय-III (ईपीएफ से संबंधित) के तहत स्थापित की जाएगी और उन प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग को निर्दिष्ट करना जिन पर उक्त योजना लागू होगी।
- (ख) निम्नलिखित का प्रावधान करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार करना जिसे कर्मचारी पेंशन योजना कहा जाएगा (i) किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग, जिस पर यह अध्याय लागू होता है, के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृति पेंशन या स्थायी पूर्ण विकलांगता पेंशन; (ii) ऐसे कर्मचारियों के लाभार्थियों को देय विधवा या विधुर पेंशन, बच्चों को पेंशन या अनाथ पेंशन; और (iii) नामांकित व्यक्ति पेंशन।

(ग) किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग, जिस पर अध्याय-III (ईपीएफ से संबंधित) लागू होता है; के कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना नामक एक योजना तैयार करना।

(घ) स्व-रोजगार श्रमिकों या किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को इस संहिता के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए कोई अन्य योजना या योजनाएं तैयार करना।

25. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत निर्धारित नियोक्ता के दायित्व पर चर्चा करें।

उत्तर. नियोक्ता को ऐसे रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखने होंगे जिनमें निम्नलिखित विवरण हों:

i) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के दिनों की संख्या;

ii) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के घंटों की संख्या;

iii) वेतन भुगतान;

iv) छुट्टी, छुट्टी वेतन, ओवरटाइम काम और उपस्थिति के लिए वेतन;

v) कर्मचारी पहचान संख्या, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;

vi) खतरनाक घटनाओं, दुर्घटनाओं, चोटों की संख्या जिनके संबंध में नियोक्ता द्वारा मुआवजे का भुगतान किया गया है और क्रमशः अध्याय IV और अध्याय VI से संबंधित ऐसे मुआवजे की राशि;

vi i) अध्याय III और अध्याय IV के संबंध में किसी कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता द्वारा की गई वैधानिक कटौतियाँ;

vi ii) भवन और अन्य निर्माण कार्य के संबंध में भुगतान किए गए उपकर का विवरण;

ix) निर्दिष्ट दिन पर कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदात्मक या निश्चित अवधि का रोजगार);

x) किसी विशेष अवधि के दौरान भर्ती किए गए व्यक्ति; (xi) कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण; और

xi) वे रिकियाँ जिनके लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।

नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि :

कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर ऐसे तरीके और प्रारूप में नोटिस प्रदर्शित करें जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हों;

कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा वेतन पर्चियाँ जारी करना; और

ऐसा रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के दौरान दाखिल करना जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हों।

26. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अपराधों का प्रशमन क्या है? इसमें क्या प्रक्रिया शामिल है?

उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 138 और संबंधित नियम 56 यहां लागू होते हैं।

- (1) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के लिए फॉर्म-XXI V में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक प्रशमन नोटिस जारी करेगा, जो धारा 138 के तहत प्रशमन योग्य है।
- (2) जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है वह फॉर्म-XXI V के भाग III में अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर पूरी प्रशमन राशि इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से या अन्यथा जमा कर सकता है।
- (3) कंपाऊंडिंग अधिकारी कंपोजिशन राशि की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर फॉर्म-XXI V के भाग IV में ऐसे व्यक्ति को कंपोजिशन प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिससे कंपोजिशन नोटिस की संतुष्टि में ऐसी राशि प्राप्त की गई है।
- (4) यदि कोई व्यक्ति, जिसे ऐसा नोटिस दिया गया है, निर्धारित समय के भीतर कंपोजीशन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सक्षम न्यायालय या अपराध जिसके संबंध में कंपाऊंडिंग नोटिस जारी किया गया था, के समक्ष अभियोजन शुरू किया जाएगा।
- (5) अभियोजन को संस्थित करने के पश्चात् प्रशमन
- (ए) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के बाद अदालत किसी भी समय किसी भी प्रशमन योग्य अपराध का प्रशमन कर सकती है।
- (बी) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के प्रावधान ऐसे प्रशमन पर लागू होंगे।

27. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कैरियर सेंटर क्या है?

उत्तर. कैरियर सेंटर रोजगार कार्यालयों का स्थान लेंगे और इसमें कोई भी कार्यालय (रोजगार कार्यालय, स्थान या पोर्टल सहित) शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा कैरियर सेवाएं (पंजीकरण, संग्रह और सूचना प्रस्तुत करना, या तो रजिस्टर रखकर या अन्यथा, मैन्युअल रूप से, डिजिटल रूप से, वस्तुतः या किसी अन्य माध्यम से) प्रदान करने के लिए निर्धारित तरीके, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, से स्थापित और अनुरक्षित किया जाता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ आम तौर पर या विशेष रूप से निम्न से संबंधित हो सकता है- (i) ऐसे व्यक्ति जो कर्मचारियों को नियोजित करना चाहते हैं; (ii) जो व्यक्ति रोजगार चाहते हैं; (iii) रिक्तियों की घटना; और (iv) ऐसे व्यक्ति जो स्व-रोजगार शुरू करने के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श या मार्गदर्शन चाहते हैं।

28. क्या महामारी या आपदा के समय केंद्र सरकार के पास कोई विशेष शक्ति निहित है?
- उत्तर. हाँ। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 144 केंद्र सरकार की शक्ति का विवरण देती है। महामारी, स्थानिक या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में उस प्रतिष्ठान, जिस पर अध्याय III या अध्याय IV, जैसा भी मामला हो, लागू होता है, के संबंध में अध्याय III या अध्याय IV के तहत देय नियोक्ता के योगदान, या कर्मचारी के योगदान, या दोनों, जैसा भी मामला हो, को एक समय में तीन महीने तक की अवधि के लिए स्थगित या कम कर सकती है। यह केवल ईपीएफ और ईएसआई योगदान पर लागू होता है।
29. सामाजिक सुरक्षा निधि क्या है?
- उत्तर. संहिता केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करना अनिवार्य करती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 141 (1) में बताया गया है कि यहां केंद्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों, गिर्ग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित किया जाएगा। निधि का प्रमुख स्रोत सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अपराधों के प्रशमन और निर्धारित किसी भी अन्य स्रोत के माध्यम से एकत्र की गई राशि होगी।
30. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत सामाजिक सुरक्षा संगठनों की ऑडिटिंग कैसे निर्धारित की जाती है?
- उत्तर. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 116 इसका विवरण देती है। प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन के खातों का वार्षिक ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाना है और ऐसे ऑडिट के संबंध में उनके द्वारा किया गया कोई भी व्यय संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।
